PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

**Hindustan, Delhi**
**Mon, 12 Jun 2017, Page 13**
**Width: 25.32 cms, Height: 15.66 cms, a4r, Ref: 31.2017-06-12.115**

# न्यूनतम आय के प्रस्ताव पर विचार

नई दिल्ली | एजेंसियां

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि वह वर्ष 2016-17 की आर्थिक समीक्षा में दो अनूठे सुझाव सार्वजनीन न्यूनतम आय (यूबीआई) तथा फंसे कर्ज से निपटने के लिए बैड बैंक गठित करने पर चर्चा कर रहे हैं।

वित्त मंत्री ने हालांकि, यह भी कहा कि राजनीतिक सीमाओं को देखते हुए फिलहाल यूबीआई का विचार व्यवहारिक नीतिगत विकल्प नहीं जान पड़ता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (आईआईटी), दिल्ली के एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

## तैयारी

- वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा में मिले प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा
- फंसे कर्ज से निपटने के लिए बैड बैंक के गठन पर भी बात

वित्त मंत्री ने यह भी जोर देकर कहा कि नीति निर्माता विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान का लगातार विस्तार करें। समीक्षा के अनूठे विचारों के बारे में उन्होंने कहा कि यह चुनौती बनी हुई है कि सब्सिडी को कैसे लक्षित तरीके से पहुंचाया जाए। जेटली ने कहा कि इस साल भी समीक्षा में महत्वपूर्ण विचार दिया गया है कि हम कैसे सब्सिडी दें।

आखिर पूरी सब्सिडी का विकल्प क्या हो। उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी की जगह सर्वजनीन न्यूनतम आय (लक्षित गरीबों के एक तबके के लिए) को लाना चाहते है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियम द्वारा तैयार आर्थिक समीक्षा में बैड बैंक का भी विचार दिया गया है जिसमें बैंकों की की सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) हो ताकि शेष बैंक प्रणाली अपना काम-काज कर सके। जेटली ने कहा कि मैं इन दोनों सुझावों पर उनके साथ चर्चा करता रहा हूं।